

धन्य एम
बनाम
केरल राज्य और अन्य।

(आपराधिक अपील क्रमांक 2897/2025)

06 जून 2025

(न्यायमूर्ति श्री संजय करोल* एवं न्यायमूर्ति श्री मनमोहन)

विचारणीय बिंदु

क्या निरुद्ध व्यक्ति की निरोधात्मक हिरासत विधि के अनुसार है।

शीर्ष टिप्पणियाँ[†]

केरल असामाजिक गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 2007 – धारा 3, 2(ज), (ण) – धारा 3(1) के तहत दिया गया निरोध आदेश, क्या मान्य है:

अभिनिर्धारित: नहीं – धारा 2(ज) में कहा गया है कि जो व्यक्ति 'लोक व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक' गतिविधियों में लिप्त होता है, वह अधिनियम के अंतर्गत आता है – वर्तमान मामले में, तथ्य और परिस्थितियाँ लोक व्यवस्था की स्थिति की श्रेणी में नहीं आती हैं – निरोध आदेश में कोई कारण नहीं बताया गया है कि निरुद्ध व्यक्ति के कार्य राज्य की लोक व्यवस्था के विरुद्ध कैसे थे – निवारक निरोध की शक्ति की असाधारण प्रकृति को देखते हुए, निरोधक प्राधिकारी द्वारा यह कारण नहीं बताया गया कि निरुद्ध व्यक्ति के कार्य ऐसी असाधारण शक्ति के प्रयोग को क्यों और कैसे आवश्यक बनाते हैं – राज्य को निरोधक निरोध कानून के तहत रखने के बजाय, निरुद्ध व्यक्ति की जमानत रद्द करने के लिए अग्रसर होना चाहिए – धारा 3 के तहत शक्ति का प्रयोग कानून में न्यायसंगत नहीं था – निरोध आदेश और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 3(1) के तहत पारित उक्त आदेश की पुष्टि करने वाला उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय रद्द किया जाता है – केरल साहूकार अधिनियम, 1958 – केरल अत्यधिक ब्याज प्रभारित करने का निषेध अधिनियम, 2012 – भारतीय दंड संहिता, 1860 – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989। [कंडिका 17, 19, 21-23]

केरल असामाजिक गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 2007 – धाराएँ 2(ज), (ण), 3, 7, 12 – अधिनियम की योजना और उद्देश्य – चर्चा की गई। [कंडिका 12-15]

भारत का संविधान – अनुच्छेद 22 – निवारक निरोध – असाधारण शक्ति, इसका प्रयोग:

अभिनिर्धारित: निवारक निरोध एक असाधारण शक्ति है जिसका उपयोग विरल रूप से किया जाना चाहिए – यह आगे के अपराधों के किए जाने की आशंका में एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करती है, और इसलिए, इसका उपयोग प्रकृति के सामान्य क्रम में नहीं किया जाना चाहिए – निवारक निरोध की शक्ति अनुच्छेद 21 का एक अपवाद है और इसलिए, इसे मुख्य नियम के अपवाद के रूप में और केवल दुर्लभ मामलों में ही लागू किया जाना चाहिए। [कंडिका 9]

उद्धृत न्यायदृष्टान्त

रेखा बनाम तमिलनाडु राज्य [2011] 4 एससीआर 740: (2011) 5 एससीसी 244; मुर्तुजा हुसैन चौधरी बनाम नागालैंड राज्य और अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 502; इच्छू देवी बनाम

भारत संघ [1981] 1 एससीआर 640: (1980) 4 एससीसी 531; बांका स्नेहा शीला बनाम तेलंगाना राज्य [2021] 8 एससीआर 978: (2021) 9 एससीसी 415; एसके. नाजनीन बनाम तेलंगाना राज्य (2023) 9 एससीसी 633; नैनावत बुज्जी आदि बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 367; अमीना बेगम बनाम तेलंगाना राज्य [2023] 11 एससीआर 958: (2023) 9 एससीसी 587 – संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

केरल असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 2007; केरल साहूकार अधिनियम, 1958; केरल अत्यधिक ब्याज प्रभारित करने का प्रतिषेध अधिनियम, 2012; दंड संहिता, 1860 (या भारतीय दंड संहिता, 1860); अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989; भारत का संविधान

कीवर्ड की सूची

निवारक निरोध; निरोधित व्यक्ति; निरोध का आदेश; निरोध आदेश; "लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हानिकारक"; लोक व्यवस्था की स्थिति; 'गुंडा', 'कुख्यात गुंडा'; 'ज्ञात गुंडा'; जिला मजिस्ट्रेट; निरोधक प्राधिकारी; निरोधित व्यक्ति की जमानत रद्द करना; बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट; केरल राज्य; असामाजिक क्रियाकलाप; अवैध निरोध; निवारक निरोध की शक्ति; असाधारण शक्ति; निरोध आदेश अपास्त.

किससे उद्धृत मामला

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील क्रमांक 2897/ 2025

डब्लूपी सीआरएल संख्या 874/2024 में केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम के निर्णय और आदेश दिनांक 04.09.2024 से क्रमशः

पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण

अजय प्रभु एस, अमित सांगवान, सिबी कारगिल, सुश्री आर. शासे। अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण हर्षद वी. हमीद, दिलीप पूलकोट, श्रीमती एशली हर्षद। अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थीगण

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति श्री संजय करोल

अनुमति प्रदान की गयी।

- वर्तमान अपील एर्नाकुलम स्थित केरल उच्च न्यायालय द्वारा डब्लूपी सीआरएल संख्या 874/2024 में पारित दिनांक 4 सितंबर, 2024 के अंतिम निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा पलक्कड़ के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 20 जून, 2024 के उस आदेश की पुष्टि की गई, जिसमें अपीलकर्ता के पति राजेश¹ को केरल असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 2007² की धारा 3 के तहत कारागार में निवारक निरोध में रखे जाने का निर्देश दिया गया था।
- वर्तमान अपील को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि निरोधी 'रितिका फाइनैस' नाम से एक पंजीकृत ऋण फर्म चला रहा है। 20 जून, 2024 को, पलक्कड़ के जिला मजिस्ट्रेट ने, पलक्कड़ जिला पुलिस प्रमुख

द्वारा दिनांक 29 मई, 2024 के सिफारिश संख्या 54/कैंप/2024-पी-केएए(पी)ए के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 3(1) के तहत एक निरोध आदेश जारी किया। उसमें कहा गया था कि निरोधी जिले का 'कुख्यात गुंडा' है और समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। इस घोषणा के लिए निम्नलिखित मामलों पर विचार किया गया था:

- i. कसाबा पुलिस स्टेशन में केरल साहूकार अधिनियम, 1958 की धारा 17, और केरल अत्यधिक ब्याज लेने का प्रतिषेध अधिनियम, 2012 की धारा 3, 9(1)(क) के तहत अपराध संख्या 17/2020।
- ii. टाउन साउथ पुलिस स्टेशन में केरल साहूकार अधिनियम, 1958 की धारा 17 के साथ पठित धारा 3, और केरल अत्यधिक ब्याज लेने का प्रतिषेध अधिनियम, 2012 की धारा 3 के साथ पठित धारा 9(क)(ख) के तहत अपराध संख्या 220/2022।
- iii. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 294(ख), 506(1), और केरल साहूकार अधिनियम, 1958 की धारा 17 के साथ पठित धारा 3, तथा केरल अत्यधिक ब्याज प्रभारित करने का प्रतिषेध अधिनियम, 2012 की धारा 3 के साथ पठित धारा 9(क)(ख) के तहत अपराध संख्या 221/2022।
- iv. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 341, 323, 324, 326; केरल साहूकार अधिनियम, 1958 की धारा 17; केरल अत्यधिक ब्याज प्रभारित करने पर रोक अधिनियम, 2012 की धारा 4, और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2), (वक), 3(1)(द), 3(1)(ध) के तहत अपराध संख्या 401/2024।

4. नतीजतन, निरोधित व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। दिनांक 20 जून, 2024 के निरोध आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने निरोध आदेश को चुनौती देते हुए और अपने पति, राजेश, के अवैध निरोध के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 - केरल राज्य से बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए प्रार्थना करते हुए केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।
5. आक्षेपित निर्णय और आदेश के माध्यम से, केरल उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्षों के साथ निरोध आदेश को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया है:
 - क. निरोधित व्यक्ति के विरुद्ध मामलों का परिणाम दोषमुक्ति होगा या नहीं, यह एक ऐसा कार्य नहीं है जो निवारक निरोध का आदेश पारित करते समय निरोधक प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है।
 - ख. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकारिता में, न्यायालय अपने समक्ष रखे गए सामग्रियों के आधार पर प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील में नहीं बैठता है।
 - ग. आक्षेपित कार्रवाई में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया गया है।
6. उससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की है। अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए चुनौती का महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि निरोधित व्यक्ति के विरुद्ध सभी मामलों में, वह जमानत पर है और न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन कर रहा है।
7. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना और दाखिल किए गए लिखित अभिवचनों का अवलोकन किया। दिनांक 10 दिसंबर 2024 के आदेश के माध्यम से, निरोधित व्यक्ति को इस न्यायालय द्वारा रिहा कर दिया गया था, क्योंकि अधिनियम के तहत निरोध की अधिकतम अवधि पूरी हो चुकी थी।

8. इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या निरोधित व्यक्ति का निवारक निरोध कानून के अनुसार है।
9. यह सुस्थापित है कि निवारक निरोध का प्रावधान राज्य के हाथों में एक असाधारण शक्ति है जिसका उपयोग संयम से किया जाना चाहिए। यह भविष्य में और अपराधों के किए जाने की आशंका में एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करता है, और इसलिए, इसका उपयोग सामान्य प्रकृति के क्रम में नहीं किया जाना चाहिए। निवारक निरोध की शक्ति को संविधान में ही, अनुच्छेद 22(3)(ख) के तहत मान्यता प्राप्त है। हालाँकि, इस न्यायालय ने **रेखा बनाम तमिलनाडु राज्य** के मामले में इस बात पर जोर दिया है कि निवारक निरोध की शक्ति अनुच्छेद 21 का एक अपवाद है और इसलिए, इसे मुख्य नियम के अपवाद के रूप में और केवल दुर्लभ मामलों में ही इस तरह लागू किया जाना चाहिए।
10. उपरोक्त स्थिति को, हाल ही में इस न्यायालय द्वारा **मूर्तजा हुसैन चौधरी बनाम नागालैंड राज्य और अन्य** के मामले में, संक्षेप में इस प्रकार सारगर्भित किया गया था:

"2. निवारक निरोध एक कठोर उपाय है जिसके द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर किसी दंड कानून के तहत मुकदमा नहीं चलाया गया है और जिसे दोषी नहीं ठहराया गया है, उसकी अपेक्षित आपराधिक गतिविधियों को कम करने के उद्देश्य से एक निश्चित अवधि के लिए निरुद्ध और परिरुद्ध किया जा सकता है। हालाँकि, यह चरम तंत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(3)(ख) द्वारा अनुमत है। महत्वपूर्ण रूप से, अनुच्छेद 22 निवारक निरोध को प्रभावी करते समय पालन किए जाने वाले कठोर मानदंडों को भी निर्धारित करता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 22 संसद को निवारक निरोध से संबंधित शर्तों और विधियों को निर्धारित करने वाला कानून बनाने की बात करता है। अधिनियम 1988 ऐसा ही एक कानून है जिसे संसद द्वारा मादक द्रव्यों और मनःप्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से निवारक निरोध को अधिकृत करते हुए अधिनियमित किया गया था। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि, चूंकि निवारक निरोध किसी व्यक्ति को आपराधिक अपराध के लिए मुकदमा चलाए बिना और दोषी ठहराए बिना, उसे एक निश्चित समय के लिए निरुद्ध करके उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करता है, इसलिए संवैधानिक और वैधानिक मानदंडों और आवश्यकताओं के उचित अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।"

(जोर दिया गया)

11. इसके अलावा, निवारक निरोध की शक्ति की असाधारण प्रकृति को देखते हुए, इस न्यायालय ने **इच्छु देवी बनाम भारत संघ** के मामले में, निरोधक प्राधिकारी पर यह सिद्ध करने का भार डाला कि ऐसे कार्य अनुच्छेद 21 के अनुरूप कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप हैं। इसी प्रकार, **बंका स्नेहा शीला बनाम तेलंगाना राज्य** के मामले में, इस न्यायालय ने दोहराया कि निवारक निरोध के कार्य को संविधान के अनुच्छेद 21 और विचाराधीन कानून के साथ जाँचा जाना चाहिए।
12. इस चरण में, हमें अधिनियम की योजना और उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए, जिसके तहत विवादित निरोध आदेश पारित किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य केरल राज्य में कुछ असामाजिक गतिविधियों के प्रभावी निवारण का प्रावधान करना है। धारा 2(ज) 'गुंडा' को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल होता है। इसमें अवैध शराब बेचने वाले, जालसाजी करने वाले, मादक पदार्थों से संबंधित अपराधी, और सूदखोर, अन्य व्यक्तियों के साथ शामिल हैं। धारा 2(ण) 'ज्ञात गुंडा' के लिए वर्गीकरण निर्धारित करती है, जो एक ऐसा गुंडा है जो रहा है -"

- i. एक ऐसे अपराध का दोषी पाया गया हो जो धारा 2(ज) में उल्लिखित श्रेणियों के अंतर्गत आता हो; या
 - ii. दो अलग-अलग दृष्टांतों में व्यक्तियों द्वारा शुरू की गई शिकायतों पर किसी भी जाँच या सक्षम न्यायालय में, जो एक ही संव्यवहार का हिस्सा नहीं हैं, धारा 2(ज) में परिभाषित 'गुंडा' शब्द के अर्थ के भीतर कोई कार्य किया हुआ पाया गया।
13. अधिनियम की धारा 3 के तहत, इस प्रकार प्राधिकृत जिला मजिस्ट्रेट या सरकार, केरल राज्य के भीतर असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए, एक 'ज्ञात गुंडा' के निरोध का आदेश दे सकती है।
 14. धारा 7 यह अधिदेशित करती है कि निरोधित व्यक्ति को, निवारक निरोध के पाँच दिनों के भीतर, निरोध के आधारों का, संबंधित दस्तावेजों सहित, प्रकटीकरण किया जाए।
 15. अधिनियम की धारा 12 यह निर्दिष्ट करती है कि किसी भी व्यक्ति के लिए निरोध की अवधि छह महीने से अधिक नहीं होगी।
 16. उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों पर आते हुए, हमारा सुविचारित मत है कि अधिनियम की धारा 3 के तहत शक्ति का प्रयोग कानून में न्यायसंगत नहीं था।
 17. धारा 2(ज) के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि जो व्यक्ति 'लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हानिकारक' गतिविधियों में लिप्त होता है, उसे इस अधिनियम के तहत कवर करने की मांग की गई है। इस न्यायालय ने **एस.के. नाज़नीन बनाम तेलंगाना राज्य** मामले में लोक व्यवस्था के साथ-साथ कानून और व्यवस्था की स्थितियों के बीच के अंतर पर जोर दिया था:

"18. हाल ही के दो निर्णयों [बंका स्नेहा शीला बनाम तेलंगाना राज्य, (2021) 9 एससीसी 415 : (2021) 3 एससीसी (क्रि.) 446; मल्लादा के. श्री राम बनाम तेलंगाना राज्य, (2023) 13 एससीसी 537 : 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 424] में, इस न्यायालय ने उसी अधिनियम, अर्थात् वर्तमान तेलंगाना अधिनियम, के तहत पारित निरोध आदेशों को रद्द कर दिया था। यह मुख्य रूप से राम मनोहर लोहिया [राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य, 1965 एससीसी ऑनलाइन एससी 9] के निर्णय पर भरोसा करते हुए और यह मानते हुए किया गया था कि निरोध आदेश उचित नहीं थे क्योंकि वे लोक व्यवस्था की स्थिति से नहीं, बल्कि कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपट रहे थे।"

(जोर दिया गया)
 18. इसी प्रकार, **नेनावथ बुज़ी इत्यादि बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य** के मामले में, इस न्यायालय ने यह अवलोकन किया :

"32. महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या निरुद्ध व्यक्ति की गतिविधियाँ लोक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल थीं। जबकि 'विधि और व्यवस्था' अभिव्यक्ति का दायरा अधिक व्यापक है, क्योंकि विधि का उल्लंघन सदैव व्यवस्था को प्रभावित करता है, वहीं 'लोक व्यवस्था' का दायरा संकीर्ण होता है, और यह केवल ऐसे उल्लंघन से ही प्रभावित हो सकता है, जो समुदाय या आम जनता को प्रभावित करता हो। लोक व्यवस्था, समुदाय के जीवन की समरूप गति है, चाहे देश को समग्र रूप से लिया जाए या किसी विशिष्ट इलाके को। 'विधि और व्यवस्था' और 'लोक व्यवस्था' के क्षेत्रों के बीच का अंतर, समाज पर प्रश्रुत कार्य की पहुँच की सीमा और मात्रा का है। यह समुदाय के

जीवन की समरूप गति को बाधित करने की कार्य की क्षमता है जो इसे लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के लिए हानिकारक बनाती है। यदि कोई उल्लंघन, अपने प्रभाव में, आम जनता के एक व्यापक वर्ग के बजाय सीधे तौर पर शामिल केवल कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित है, तो यह केवल विधि और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकता है। दूसरे शब्दों में, विधि और व्यवस्था तथा लोक व्यवस्था के क्षेत्रों के बीच का वास्तविक अंतर न केवल कार्य की प्रकृति या गुणवत्ता में निहित है, बल्कि समाज पर उसकी पहुँच की मात्रा और सीमा में है। समान प्रकृति के कार्य, लेकिन विभिन्न संदर्भों और परिस्थितियों में किए गए, अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ पैदा कर सकते हैं। एक मामले में, यह केवल विशिष्ट व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है, और इसलिए केवल विधि और व्यवस्था की समस्या को छूता है, जबकि दूसरे में यह लोक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। अतः, कार्य स्वयं अपनी गंभीरता का निर्धारक नहीं होता। अपनी गुणवत्ता में यह अन्य समान कार्यों से भिन्न नहीं हो सकता है, लेकिन अपनी क्षमता में, यानी समाज पर इसके प्रभाव में, यह बहुत भिन्न हो सकता है।"

(जोर दिया गया)

19. कानून की उपरोक्त व्याख्याओं के अनुरूप, हमारे विचार से, संलग्न तथ्य और परिस्थितियाँ लोक व्यवस्था की स्थिति की श्रेणी में नहीं आती हैं। निरोध आदेश में की गई टिप्पणियों में ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया है कि निरुद्ध व्यक्ति के कार्य राज्य की लोक व्यवस्था के विरुद्ध कैसे हैं। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, निवारक निरोध की शक्ति की असाधारण प्रकृति को देखते हुए, निरोधक प्राधिकारी द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है कि निरुद्ध व्यक्ति के कार्य इस तरह की असाधारण शक्ति के प्रयोग को क्यों और कैसे न्यायसंगत ठहराते हैं।
20. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी द्वारा उसमें यह कहा गया है कि निरोधित व्यक्ति उन मामलों में उस पर लगाई गई जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, जिन पर निरोध आदेश पारित करने के लिए विचार किया गया है। हालाँकि, प्रासंगिक रूप से, प्रतिवादी-राज्य द्वारा इन चार मामलों में से किसी में भी, यदि कोई हो, ऐसी शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया है, और तो और, उन्हें यहाँ स्पष्ट रूप से बताया भी नहीं गया है।
21. इस न्यायालय ने **एस.के. नाज़नीन** (उपरोक्त) मामले में यह टिप्पणी की थी कि राज्य को निवारक निरोध कानून के तहत निरोधित व्यक्ति को रखने के बजाय, उसकी जमानत रद्द करने के लिए आवेदन करना चाहिए, जो कि उपयुक्त उपचार नहीं है। इसी तरह, **अमीना बेगम बनाम तेलंगाना राज्य** के मामले में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

"59. ... यह नोट करना प्रासंगिक है कि उन तीन आपराधिक कार्यवाहियों में जहाँ निरुद्ध व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया गया था, राज्य द्वारा जमानत रद्द करने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया था। इसके आलोक में, अधिनियम के प्रावधानों का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए था, जो कि एक असाधारण कानून है, जबकि साधारण आपराधिक कानून ने आपत्तियों को दूर करने के लिए पर्याप्त साधन प्रदान किए थे जिनके कारण आक्षेपित निरोध आदेश जारी हुआ। जमानत आदेशों के विरुद्ध अपील करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हो सकते थे, लेकिन परिस्थितियों में निवारक निरोध के कानून के असाधारण उपाय का सहारा लेने के लिए साधारण आपराधिक प्रक्रिया को दरकिनार करना उचित नहीं था।"

60. विजय नारायण सिंह बनाम बिहार राज्य [विजय नारायण सिंह बनाम बिहार राज्य, (1984) 3 एससीसी 14 : 1984 एससीसी (क्रि.) 361] मामले में, माननीय न्यायमूर्ति ई.एस. वेंकटरमैया (जैसा कि वे तब मुख्य न्यायाधीश थे) ने यह टिप्पणी की थी: (एससीसी पृष्ठ 35-36, पैरा 32)

"32. ... यह सुस्थापित है कि निवारक निरोध का कानून एक कठोर कानून है और इसलिए इसे सख्ती से समझा जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में न पड़े, जब तक कि उसका मामला प्रासंगिक कानून के चार कोनों के भीतर पूरी तरह से न आता हो। निवारक निरोध के कानून का उपयोग केवल एक अभियुक्त के पंख काटने के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो आपराधिक अभियोजन में शामिल है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को तब निरोध में रखने के लिए नहीं है जब सामान्य आपराधिक कानून के तहत जमानत के आदेशों का जारी होना रोकना संभव न हो, जब तक कि उपलब्ध सामग्री ऐसी न हो जो ऐसे निरोध को अधिकृत करने वाले कानूनी प्रावधानों की आवश्यकताओं को पूरा करती हो। जब किसी व्यक्ति को एक सक्षम आपराधिक न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ा जाता है, तो निवारक निरोध के आदेश की वैधता की जांच करने में अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए, जो उसी आरोप पर आधारित होता है जिस पर आपराधिक न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाना है।"

(जोर दिया गया)

22. कानून की उपरोक्त व्याख्याओं को ध्यान में रखते हुए, हमें कोई संदेह नहीं है कि निरोध आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता। निरोधक प्राधिकारी द्वारा आदेश में इंगित परिस्थितियाँ राज्य के लिए सक्षम न्यायालयों में जाकर जमानत रद्द करवाने के लिए पर्याप्त आधार हो सकती हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हीं परिस्थितियों ने उसके निवारक निरोध को आवश्यक बना दिया। हम स्पष्ट करते हैं कि यदि प्रतिवादी-राज्य द्वारा निरोधित व्यक्ति की जमानत रद्द करवाने के लिए ऐसा कोई आवेदन किया जाता है, तो उस पर यहाँ दिए गए पर्यवेक्षणों से अप्रभावित रहते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए।
23. अतः, दिनांक 20 जून, 2024 का निरोध आदेश और केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम द्वारा डब्ल्यूपी सीआरएल संख्या 874/2024 में पारित दिनांक 4 सितंबर, 2024 का आक्षेपित निर्णय एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। इस मामले के परिचर तथ्यों और परिस्थितियों में, अपील अनुमत की जाती है। लंबित आवेदन (या आवेदनों), यदि कोई हो, निराकृत माने जाएँगे।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकार की गई।

† शीर्ष टिप्पणियाँ तैयार की गयीं: द्वारा दिव्या पांडे

* लेखक

(प्रतीक राय द्वारा अनुवादित)

- 1 इसके पश्चात "निरोधित व्यक्ति"
- 2 इसके पश्चात "अधिनियम"
- 3 (2011) 5 एससीसी 244
- 4 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 502
- 5 (1980) 4 एससीसी 531
- 6 (2021) 9 एससीसी 415
- 7 (2023) 9 एससीसी 633
- 8 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 367
- 9 (2023) 9 एससीसी 587